बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 188 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 12 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

पश्चिम एशिया संकट पर भारत अलर्ट, राजनाथ सिंह ने मंत्रियों साथ की हाईलेवल मीटिंग

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति पर नजर रखने के लिए गठित मंत्रियों के अनौपचारिक अधिकार प्राप्त समूह की बैठक की अध्यक्षता की। आप को बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे माल की कीमतों में आई तेजी के बीच एडहेसिव (चिपकाने वाले उत्पाद) और निर्माण रसायन बनाने वाली कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज कीमतों में एक और दौर की वृद्धि पर विचार कर रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक सुधांशु वत्स ने यह जानकारी दी। फेविकोल, डॉ. फिक्सिट, फेवीक्विक और एम-सील जैसे ब्रांड की मालिक कंपनी अप्रैल और मई में पहले ही दो बार कीमतें बढ़ा चुकी है। वत्स ने कंपनी के तिमाही नतीजों की घोषणा के बाद संवाददाताओं से कहा कि कंपनी के कच्चे माल की लागत, जो मुख्य रूप से कच्चे तेल से जुड़े उत्पादों पर आधारित है.

सुप्रीम कोर्ट की डिजिटल पहल- सीजेआई सूर्यकांत ने लॉन्च किया वन केस वन डेटा सिस्टम

नई दिल्ली ।

देश की न्यायिक व्यवस्था को डिजिटल और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में सूर्यकांत ने सोमवार को दो बड़ी पहल की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट में दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि न्यायपालिका वन केस वन डेटा नामक नई डिजिटल पहल शुरू कर रही है।

सूचनाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा

सीजेआई ने कहा कि वन केस वन डेटा पहल के तहत देशभर के सभी हाईकोर्ट, जिला अदालतों और तालुका अदालतों की बहु-स्तरीय सूचनाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस सिस्टम में किसी केस से जुड़ी अलग-अलग अदालतों की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी, जिससे केस ट्रैकिंग और प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सकेगा।

क्या है इस पहल का उद्देश्य?

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका एक ऐसे आधुनिक केस मैनेजमेंट सिस्टम की दिशा में काम कर रही है, जो अदालतों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करे और मामलों की सुनवाई प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाए। इस पहल का उद्देश्य न्यायिक डेटा को एकीकृत करना, केस रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप से जोड़ना और अदालतों में लंबित मामलों की निगरानी को आसान बनाना है।

सीजेआई ने कहा कि यह पहल देश की अदालतों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को तेज और अधिक पारदर्शी बनाएगी। इससे न केवल न्यायिक प्रशासन को मजबूती मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों, वकीलों और न्यायपालिका से जुड़े अन्य पक्षों को भी सुविधा होगी।

सु सहायता चैटबॉट भी किया लॉन्च

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर सु सहायता नाम का एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। यह चैटबॉट नागरिकों और वादियों को सुप्रीम कोर्ट की सेवाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। सीजेआई ने बताया कि इस चैटबॉट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सहयोग से तैयार किया है। सु सहायता उपयोगकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी प्रक्रियाओं, जरूरी दिशा-निर्देशों, फाइलिंग सिस्टम, केस संबंधी जानकारी और अन्य सेवाओं तक सरल तरीके से पहुंचने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इस तकनीक का उद्देश्य आम लोगों के लिए न्यायिक सेवाओं को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है। एआई आधारित यह सिस्टम नागरिकों को वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी ढूंढने में मदद करेगा और अदालत से संबंधित प्रक्रियाओं को समझने में सहायक होगा। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारियों और बार सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं को सफल बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका आने वाले समय में भी तकनीक आधारित सुधारों पर जोर देती रहेगी, ताकि आम नागरिकों को अधिक सुगम और प्रभावी न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

वीबी-जी राम जी कानून- सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में इस दिन लागू होंगे प्रावधान, सरकार ने बताई तारीख

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 2025 के वीबी-जी राम जी कानून को लागू करने की घोषणा की है। सरकार ने एक जुलाई 2026 को वह तारीख तय की है, जिस दिन इस कानून के प्रावधान भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। इस कानून के तहत हर पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार मिलता था। यदि रोजगार मांगने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो संबंधित श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे। अधिनियम में मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर करने का प्रावधान है। भुगतान सीधे बैंक या डाकघर खातों में डीबीटी के जरिए किया जाएगा। यदि मजदूरी भुगतान में देरी होती है, तो श्रमिकों को प्रति दिन बकाया मजदूरी का 0.05 प्रतिशत मुआवजा भी मिलेगा। नई व्यवस्था में कार्यस्थलों पर उपस्थिति

फेस रिकग्निशन आधारित प्रणाली से दर्ज की जाएगी। हालांकि, नेटवर्क या तकनीकी समस्या की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी। मौजूदा ई-केवाईसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे, जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। इस अधिनियम में ग्राम पंचायतों को केंद्र में रखा गया है। परिवारों का पंजीकरण, रोजगार आवेदन स्वीकार करना, कार्यों का निष्पादन, रिकॉर्ड संधारण और विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होगी। ग्राम सभाओं की भागीदारी से स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाई जाएंगी। अधिनियम के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी ढांचा और चरम मौसम से बचाव जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों में कार्य किए जा सकेंगे। पीएम आवास योजना-ग्रामीण के कार्यों को भी मजदूरी सहायता के लिए शामिल किया जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अधिनियम के तहत होने वाले कार्यों में ठेकेदारों की अनुमति नहीं होगी। सभी कार्य श्रम आधारित होंगे और ऐसी मशीनों के उपयोग से बचा जाएगा जो मजदूरों के रोजगार को प्रभावित करें। योजना के लिए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में केंद्र और राज्य के बीच 90:10 का अनुपात रहेगा, जबकि अन्य राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए यह अनुपात 60:40 होगा।

बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। हर कार्यस्थल पर 'जनता बोर्ड' लगाया जाएगा, जिसमें कार्य, लागत और अनुमानित श्रम दिवस की जानकारी दी जाएगी। ग्राम पंचायतों को साप्ताहिक सार्वजनिक बैठकें आयोजित करनी होंगी, ताकि योजना की प्रगति और भुगतान संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। सरकार का कहना है कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम ग्रामीण रोजगार सुरक्षा, गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

दिल्ली पुलिस का केबल चोरी पर बड़ा खुलासा, 13 हॉट्सपॉट की पहचान, एक्शन में डीएमआरसी

नई दिल्ली । दिल्ली मेट्रो के लिए केबल चोर सिरदर्द बन चुके हैं. इन चोरों के कारण मेट्रो की रफ्तार कारण काफी प्रभावित हो रही है. इस बीच दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने इस मामले में एक सर्वे के जरिए बड़ा खुलासा किया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने 13 ऐसे जगहों की पहचान की है, जहां केबल चोरी का खतरा सबसे अधिक पाया गया है. इनमें 11 रूट नए हैं, जबकि दो रूट पहले से पुलिस की नजर में थे. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मेट्रो प्रशासन और पुलिस ने उन इलाकों की पहचान की है, जहां चोरी का खतरा सबसे अधिक है. इनमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर धौलाकुआं और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, कुतुब मीनार और सुल्तानपुर डिपो के बीच का रूट, मुकुंदपुर डिपो, मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन, ESI और पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशनों के बीच का रूट, और शकूरपुर तथा नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशनों के बीच का रूट शामिल है. इसके साथ ही कीर्ति नगर और रमेश नगर, वेलकम और मौजपुर, वेलकम और कृष्णा नगर, तथा गोकुलपुरी और जौहरी एन्क्लेव के बीच के रूट को और त्रिलोकपुरी-IP एस्टेट कॉरिडोर जैसे कई रूटों को भी संवेदनशील माना गया है. इनमें भी मेट्रो के दिन दो रास्तों को पहले से ही संवेदनशील माना गया था, जिनमें शास्त्री पार्क से सीलमपुर और जहांगीरपुरी के अलावा हैदरपुर मोड़ मेट्रो स्टेशनों के बीच का रूट शामिल है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान सुरक्षा और रखरखाव में कई कमियां पाई गई हैं और इन लापरवाहियों के कारण ही केबल चोरी की घटनाएं होने की संभावना जताई गई है. इनमें कुछ जगहों पर टूटी हुई चारदीवारी, संवेदनशील हिस्सों के किनारे टूटी हुई या गायब रेलिंग, और मेट्रो ट्रैक के पास बड़े पेड़ों की ठीक से छंटाई न होना शामिल है. दिल्ली पुलिस ने केबल चोरी से जुड़े कुछ आंकड़े भी साझा किए हैं. आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में केबल चोरी के 63 मामले दर्ज किए गए थे. इस मामले में 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. साल 2026 में, 15 अप्रैल तक 20 मामले दर्ज किए गए हैं. इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गौर हो कि केबल चोरी से मेट्रो का सिग्नलिंग सिस्टम प्रभावित होता है, जिसके कारण ट्रेनों को धीमी गति से चलाना पड़ता है. इन घटनाओं से मेट्रो को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. मेट्रो प्रशासन के लिए केबलों को बदलना इतना आसान नहीं होता क्योंकि इससे सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है. ऐसे में इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कई कदम उठाए हैं. इनमें चोरी की आशंका वाले इलाकों में केबलों को सीमेंट से पक्का करना, एंटी थेफ्ट क्लैंप लगाना शामिल है. इसके अलावा कटीली तारों को लगाया जा रहा है, सीसीटीवी से निगरानी को बढ़ाया जा रहा है, केबल ट्रे पर सुरक्षा कवच लगाए जा रहे हैं, और तांबे के केबलों की जगह एल्युमीनियम के केबल लगाए जा रहे हैं. गौर हो कि पिछले महीने दिल्ली पुलिस और DMRC अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक के बाद DMRC स्टाफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और दिल्ली पुलिस द्वारा मिलकर की जाने वाली गश्त को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया था.

चुनाव खत्म, जनता का इस्तेमाल खत्म, पीएम मोदी की अपील पर आप नेता ने जताई नाराजगी

हैदराबाद के सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कल (10 मई) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन युद्ध के बीच देशवासियों से अपील की कि अगले एक साल तक सोना न खरीदें, विदेश यात्रा कम करें और पेट्रोल भी कम जलाने की कोशिश करें. इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों से भारत सरकार जनता का बोझ उठा रही थी, लेकिन जैसे ही पांच राज्यों के चुनाव खत्म हुए, सरकार अब जनता का बोझ नहीं उठाएगी. संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव खत्म आपका इस्तेमाल खत्म. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अब लोगों से कहा जा रहा है कि देशभक्ति के नाम पर पेट्रोल-डीजल और गैस का इस्तेमाल कम करें, खाने के तेल का उपयोग कम करें और यहां तक कि एक साल तक शादी-ब्याह में सोना भी न खरीदें. उन्होंने कहा कि पांच राज्यों के चुनाव तक प्रधानमंत्री कहते रहे कि गैस और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सरकार के सुर बदल गए और अब जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया. चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद कमर्शियल सिलेंडर के दाम 993 रुपये कर दिए गए और घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी गई.

जनता को 10 हजार देकर फिर सड़कों पर पीटा जा रहा

संजय सिंह ने पटना का जिक्र करते हुए कहा कि पहले लोगों के खातों में 10 हजार रुपये डालकर उनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर पटना की सड़कों पर उन्हें पीटा जाता है. इसके बाद जनता को सलाह दी जाती है कि देशभक्ति के नाम पर पेट्रोल-डीजल और गैस का कम इस्तेमाल करें, सोना न खरीदें और विदेश यात्राएं भी न करें. उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में लाखों लोगों को जुटाने के लिए बसों में भर-भरकर लोगों को लाएंगे और तब पेट्रोल की कमी का कोई असर नहीं पड़ेगा.

पीएम खुद विदेश यात्रा करें, पर जनता त्याग करें

पीएम मोदी खुद विदेश यात्राएं करते हैं और अब यूएई दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन आम जनता को त्याग और बचत का पाठ पढ़ाया जा रहा है. संजय सिंह ने कहा कि उनके लोग सोना ही नहीं बल्कि पूरे देश की संपत्तियां खरीद लेंगे, जबकि आम जनता को संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया जाएगा. अंत में संजय सिंह ने कहा कि जनता से कहा जा रहा है कि देशभक्ति के नाम पर सब कुछ सहते रहो और सिर्फ मोदी जी को वोट देते रहो, यही अब जनता का काम बनकर रह गया है.

अब दिल्ली में नहीं कोई गांव- कागजों में सभी बन चुके शहर, 63 साल में 352 का कायाकल्प; पर मूलभूत सुविधाएं नदारद

नई दिल्ली ।

राजधानी में अधिकारिक रूप से एक भी गांव नहीं बचा है। हाल ही में 48 गांवों को शहरीकृत घोषित किए जाने के साथ ही दिल्ली के सभी 352 गांव शहरीकृत श्रेणी में शामिल हो गए हैं। एमसीडी ने आठ चरणों में यह प्रक्रिया पूरी की है। हालांकि छह दशक से अधिक समय तक चली इस प्रक्रिया के बावजूद अधिकांश गांवों की तस्वीर आज भी नहीं बदली है और ग्रामीणों को शहर जैसी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार है। दिल्ली में गांवों को शहरीकृत घोषित करने की शुरुआत पहले मास्टर प्लान के लागू होने के बाद वर्ष 1963 में हुई थी। उस समय 19 गांवों को शहरीकृत गांव का दर्जा दिया गया था। उसके तीन वर्ष बाद 1966 में 72 और गांवों को इस श्रेणी में शामिल किया गया। जबकि दूसरे मास्टर प्लान के दौरान वर्ष 1982 में 24 गांवों को शहरीकृत घोषित किया, जबकि 1994 में 20 अन्य गांव इस सूची में जोड़े गए। तीसरे मास्टर प्लान और लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू होने के बाद शहरीकरण की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ी। वर्ष 2017 में 89 गांवों को शहरीकृत घोषित किया गया। उसके बाद 2019 में 79 और 2021 में एक गांव को यह दर्जा मिला। अब वर्ष 2026 में शेष बचे 48 गांवों को भी शहरीकृत घोषित कर दिया गया है। इस तरह दिल्ली में गांवों का अस्तित्व प्रशासनिक रूप से पूरी तरह समाप्त हो गया है।

छह दशक बाद भी नहीं बदली गांवों की हालत

पूर्व सांसद चौ. तारीफ सिंह के अनुसार गांवों को शहरीकृत घोषित करने का उद्देश्य उन्हें शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था, लेकिन अधिकांश गांव आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई गांवों में संकरी गलियां, अव्यवस्थित निर्माण, पार्किंग की समस्या, जल निकासी की कमी और खराब सड़कें आज भी बड़ी चुनौती हैं। वहीं पूर्व महानगर पार्षद रोहताश डबास ने बताया कि शहरीकरण के नाम पर गांवों में केवल कर और नियम लागू किए गए, लेकिन सुविधाएं नहीं पहुंचीं। अधिकांश गांवों में सीवर लाइन बिछाने के अलावा कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ। कई गांवों के चारों ओर पॉश कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं, लेकिन गांव खुद चहारदीवारी में घिरे हुए अलग-थलग क्षेत्र बनकर रह गए हैं।

नियम बढ़े, नहीं बनी अनुकूल व्यवस्था

गांवों के शहरीकृत होने के बाद वहां संपत्ति कर लागू हो गया है। साथ ही भवन उपनियम, मास्टर प्लान और डीडीए के प्रावधान भी लागू हो चुके हैं। इस कारण गांवों में मकान निर्माण और पुनर्निर्माण ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांवों की पारंपरिक बसावट और संकरी गलियों को देखते हुए शहरी भवन उपनियम व्यवहारिक नहीं है। कई लोग अपने पुराने मकानों का निर्माण या मरम्मत भी आसानी से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर, गांवों में शहरी इलाकों की तरह व्यावसायिक गतिविधियों की भी पूरी अनुमति नहीं है, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है।

मास्टर प्लान और जमीनी हकीकत में अंतर

शहरी योजनाकारों का मानना है कि दिल्ली के गांवों को शहरीकृत घोषित करने की प्रक्रिया कागजों में तो पूरी हो गई, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास नहीं हो सका। गांवों की ऐतिहासिक और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखकर अलग विकास मॉडल तैयार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप गांव न पूरी तरह ग्रामीण रह पाए और न ही आधुनिक शहरी क्षेत्र बन सके।

दिल्ली पंचायत संघ के प्रमुख थान सिंह यादव का कहना है कि सरकार और संबंधित एजेंसियों को अब केवल शहरीकृत घोषित करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि गांवों के अनुरूप आधारभूत ढांचे, पार्किंग, सड़क, जल निकासी, सामुदायिक सुविधाएं और रोजगार के अवसर विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण

बढ़ते औद्योगीकरण के विभिन्न आयामों, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और मानव जीवनशैली के लिए इनके गलत उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। दूषित पर्यावरण उन घटकों को प्रभावित करता है, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ऐसे में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने, प्रकृति और पर्यावरण का महत्व समझाने के उद्देश्य से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून को मनाया जाता है। इस मौके पर विभिन्न देश अलग अलग तरीके से पर्यावरण को लेकर अपने नागरिकों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करते है। पर्यावरण दिवस मनाने की नींव 1972 में पड़ी, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहला पर्यावरण दिवस मनाया है और हर साल इस दिन को मनाने का एलान किया। विश्व में पहला पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को मनाया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन को निन्हित करते हुए 5 जून को पर्यावरण दिवस के तौर पर नामित कर लिया। पूरे विश्व में प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति खतरे में है। प्राकृतिक जीवन जीने के लिए सभी जीव को हर जरूरी चीज प्रकृति उपलब्ध कराती है। ऐसे में अगर प्रकृति प्रभावित होगी तो जीवन भी प्रभावित होगा। प्रकृति को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस मनाते हुए आमजन को जागृत किया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की एक खास थीम होती है। पिछले साल यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित थी। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम ष्टंदक त्मेजवतंजपवदए कमेमतजपपिबंजपवद ।दक कतवनहीज तमेपसपमदबम् है। इस थीम का फोकस ''हमारी भूमि'' नारे के तहत भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे पर केंद्रित रहा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम इण्डिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन (म्दकपदह ळसवइंस च्संेजपब च्वससनजपवद) पर आधारित थी। जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। अधिक पेड़ लगाना और प्रकृति की रक्षा करना प्रमुख है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह कई गैर-सरकारी संगठनों, व्यवसायों, सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्थित है। 5 जून, 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था तभी से ही यह समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्यजीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का एक मंच रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस सार्वजनिक आउटरीच के लिए एक वैश्विक मंच है, जिसमें सालाना 150 से अधिक देशों की भागीदारी होती है। प्रत्येक वर्ष, कार्यक्रम ने पर्यावरणीय कारणों की वकालत करने के लिए व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, समुदायों, सरकारों और मशहूर हस्तियों के लिए एक थीम और मंच प्रदान किया है। पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण है जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। वर्ष 2024 में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए निर्धारित थीम के अन्तर्गत विश्व के देशों ने विशेष बल दिया है। मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता व आजीविका के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिससे पारिस्थितिक रूप से सुदृढ़ भूमि प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना अनिवार्य हो जाता है। प्रत्येक बीते वर्ष के साथ, इन चुनौतियों से निपटने की तात्कालिकता और अधिक स्पष्ट हो जाती है, जिससे हमें उनके प्रभाव को कम करने के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व की अनुभूति होती है। वर्ष 2025 की थीम के तहत प्लास्टिक प्रदूषण रोकने पर जोर दिया गया और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने पर बल दिया गया। देश के मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अपील ''एक पेड़ माँ के नाम'' लगाने का असर देशवासियों पर पड़ा और उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में वर्ष 2025 में 37.21 करोड़ पौधे रोपित किये गये। इससे प्रदूषण रोकने और धरती का वनावरण बढ़ेगा। भूमि संसाधनों के लिए मरुस्थलीकरण सबसे घातक खतरों में से एक है, जो चुपचाप पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और आजीविका पर अतिक्रमण कर रहा है। पुनर्वनीकरण और वनीकरण की पहल मरू भूमि को बहाल करने और मरुस्थलीकरण को कम करने, वन्यजीवों के लिए आवश्यक आवास प्रदान करने और कार्बन पृथक्करण लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि वानिकी, संरक्षण कृषि और एकीकृत जल प्रबंधन जैसी टिकाऊ कृषि प्रथाएं मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने, सूखे के प्रति लचीलापन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में योगदान करती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रकृति के विभिन्न श्रोतों के दोहन को रोकने, अपनी भूमि को उपजाऊ एवं प्राकृतिक स्तर पर लाने के लिए अनेकों कार्य किये जा रहे है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने गत 09 वर्षों में प्रदेश में लगभग 242.13 करोड़ पौधे रोपित करते हुए वनावरण एवं भूमि की हरियाली बढ़ाई है। भूमि के कटाव को रोकने के लिए मेड़बन्दी, भूमि संरक्षण इकाई के माध्यम से बन्धे-बन्धिया, छोटे-छोटे बाँध, भूमि का समतलीकरण, कटान वाले क्षेत्रों मे सघन वृक्षारोपण आदि कार्य किये गये है। भूमि की उर्वरता, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती तथा सिंचाई की नई विधियों को अपनाते हुए भूमि को स्वस्थ रखा जा रहा है। प्रदेश सरकार गाँवों शहरों की लगातार सफाई करा रही है साथ ही प्रदूषण फैलाने वाली प्लास्टिक की पन्नियों आदि पर रोक लगाई है। परम्परागत खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप प्रयोग किये जाने वाली लकड़ी के स्थान पर सरकार ने हर गाँव, शहर के परिवारों को एल0पी0जी0 कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध कराई है।

विजय की 'शपथ यात्रा' प्रारम्भ

आज से तमिलनाडु की राजनीति में एक नये दौर की शुरूआत हो रही है जिसे 'विजय काल' कहा जा रहा है। लोकतन्त्र में ऐसे दौर आते रहते हैं, जब राजनीति पुराने समय के चंगुल से पीछा छुड़ा कर नये समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होती है। ऐसा ही हमने प. बंगाल में देखा जहां आजादी के बाद पहली बार भाजपा के नेतृत्व में शुभेन्दु सरकार कल गठित हुई। यह जीवन्त लोकतन्त्र की निशानी भी होती है क्योंकि लोकतन्त्र निरन्तर बदलाव मांगता रहता है अतः इसमें कभी भी विकल्पों की कमी नहीं होनी चाहिए। भारत की बहुदलीय प्रशासनिक प्रणाली का राज भी यही है कि इसमें जनता जरूरत पड़ने पर अपने विकल्प स्वयं तैयार कर लेती है क्योंकि अन्ततः जनता ही लोकतन्त्र की मालिक होती है। तमिलनाडु में 'थलापति' के नाम से विख्यात लोकप्रिय फिल्म अभिनेता 'चन्द्रशेखरन जोसेफ विजय' की 2024 में ही गठित 'तमिलगा वेत्री कषगम' पार्टी ने जो जीत हासिल की है वह राज्य के स्थापित राजनीतिक दलों द्रमुक व अन्ना द्रमुक की नींद उड़ाने वाली है। 234 सदस्यीय विधानसभा में उनकी पार्टी को 108 स्थान मिले हैं, जो कि सर्वाधिक हैं। अतः श्री विजय का ही संवैधानिक अधिकार बनता था कि वह चुनावों के बाद राज्य में लोकप्रिय सरकार बनायें। मगर राज्यपाल श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनसे कहा कि वह पहले बहुमत के लिए आवश्यक 118 सदस्यों की सूची उन्हें दें तभी वह स्थायी सरकार बना सकते हैं। श्री विजय को इस काम में पूरे पांच दिन लग गये और इस दौरान उन्होंने चार बार राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा ठोका लेकिन राज्यपाल ने उन्हें तभी सरकार बनाने का न्यौता दिया जब वह आश्वस्त हो गये कि श्री विजय को कम से कम 118 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इस काम में हाल तक सत्तारूढ़ द्रमुक गठबन्धन के नेता श्री एम.के. स्टालिन ने उनकी परोक्ष मदद भी की और अपने गठबन्धन की वी.सी.के. व मुस्लिम लीग पार्टियों को छूट दी कि वे विजय सरकार का समर्थन कर सकती है और साथ ही द्रमुक गठबन्धन में भी रह सकती है। श्री स्टालिन ने कहा कि विधानसभा में दूसरा सबसे बड़ा दल होने के नाते उनकी पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेगी।

इससे पहले ही श्री राहुल गांधी की कांग्रेस के पांच विधायकों ने विजय की पार्टी 'टीवीके' को अपना समर्थन द्रमुक गठबन्धन में रहते हुए ही दे दिया था। साथ ही दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के चार विधायकों ने भी विजय का समर्थन किया था। वी.सी.के. व मुस्लिम लीग के चार विधायकों को मिलाकर श्री विजय के समर्थकों की संख्या 121 हो गई (हालांकि वस्तुगत तौर पर संख्या 120 रही क्योंकि श्री विजय दो सीटों से चुनाव जीते हैं)। यह सब जुगाड़ करने में श्री विजय को पांच दिन का समय लग गया तब जाकर 9 मई को राज्यपाल ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ चेन्नई के नेहरू सभागार स्थल पर दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी की उपस्थिति उल्लेखनीय कही जायेगी क्योंकि नये मुख्यमन्त्री व राहुल गांधी में पुरानी दोस्ती बताई जाती है। श्री विजय ने मुख्यमन्त्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमन्त्री सचिवालय पहुंच कर जो सबसे पहले तीन आदेश पारित किये हैं उनसे लगता है कि वह अपने चुनावी वादों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं।

ये तीन आदेश हैं 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, प्रत्येक जिले में नशा विरोधी दस्ता और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस। इसके साथ ही उन्होंने चुनावों में और भी आर्थिक मदद देने के वादे किये हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में पहले एक श्वेत पत्र जारी करके उनके बारे में विचार करेंगे। राज्य पर फिलहाल नौ लाख करोड़ रुपए से ऊपर का ऋण है। दरअसल श्री विजय को उनकी फिल्मी छवि के अनुसार राज्य की जनता 'जन नायगम् और थलापति' कहती है जिसका मतलब होता है लोकनायक और कमांडर। इस प्रकार उनकी छवि एक महानायक की बनी हुई है, अतः राज्य का प्रशासन चलाते हुए उन्हें अपनी जन छवि का भी विशेष ध्यान रखना होगा जो कि वर्तमान राजनीतिक दौर में आसान काम नहीं है। वैसे अगर राज्य की राजनीति के इतिहास को देखें तो उनसे पहले भी फिल्मी हस्तियां राज्य की मुख्यमन्त्री रही हैं जिनमें फिल्मी गीतकार व पटकथा लेखक स्व. एम. करुणानिधि से लेकर अभिनेता एम.जी. रामचन्द्रन व अभिनेत्री जयललिता के नाम आते हैं। ये 1969 से लेकर जीवन पर्यन्त मुख्यमन्त्री बनते और उतरते रहे मगर राज्य की राजनीति इन्हीं तीन व्यक्तियों के उत्तराधिकार पर ही चलती रही। इस दौरान फिल्म अभिनेता विजयकान्त व कमल हासन ने भी अपनी-अपनी पार्टियां गठित करके राजनीति में भाग्य आजमाया मगर इन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। इनमें से विजयकान्त तो तमिलनाडु विधानसभा में एक बार विपक्ष के नेता जरूर बनने में सक्षम हो सके मगर वह सत्ता की धुरी नहीं बन सके। कमल हसन को तो अन्ततः राज्यसभा सदस्य बनने के लिए द्रमुक की शरण में ही जाना पड़ा। इनके बाद श्री विजय एक मात्र ऐसे अभिनेता से नेता बने व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी लोकप्रियता के बूते पर राजनीति को अपनी चेरी बनाने में सफलता हासिल की है और तमिलनाडु की राजनीति से जाति व वर्गवाद को समाप्त करके सही मायनों में सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने का संकल्प किया है। उनके साथ टी.वी.के. के जिन अन्य नौ विधायकों ने शपथ ली है वे भी तमिल समाज की इसी विविधता को दर्शाते हैं।

सम्पादकीय...

वीआईपी सुरक्षा क्यों?

नर्मदा नदी के बर्गी बांध के दुखद हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक आम नागरिक की टिप्पणी ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर किया। उसका कहना था कि जब देश में ऊर्जा संकट बढ़ रहा है और अनावश्यक दुर्घटनाओं में कीमती जीवन समाप्त हो रहे हैं तो वीआईपी सुरक्षा के नाम पर हजारों गाड़ियां और सुरक्षाकर्मी क्यों रात-दिन भागते रहते हैं? जबकि यही सुरक्षा कर्मी अगर यातायात, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा नियमों के कड़े अनुपालन और आपदा प्रबंधन के लिए तैनात रहें तो आम जनता को कितनी राहत मिलेगी? भारतीय मूल का 38 वर्षीय हिमांशु गुलाटी नॉर्वे का तीसरी बार सांसद है और वहां का उप-कानून मंत्री भी। उसे कोई वीआईपी सुरक्षा नहीं मिली हुई। उसने मुझे बताया कि नॉर्वे की पिछली प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग जब एक बार उसके घर रात्रि भोज पर आईं तो वे बिना किसी सुरक्षा बंदोबस्त के स्वयं कार चला कर आईं और सीधे रसोई में जा कर रसोइए से हालचाल पूछने लगीं। सिडनी से मेरी मित्र विमला ने पिछला लेख पढ़ कर फोन पर बताया कि कुछ दिन पहले वो सिनेमा घर में फिल्म देख रही थीं। अचानक उसकी निगाह पड़ी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पर जो उसी पंक्ति में बिना किसी सुरक्षा के फिल्म देख रहे थे। अमरीका और यूरोप के देशों में अक्सर आपको वर्तमान व निवर्तमान राष्ट्राध्यक्ष आम आदमी की तरह बाजारों में घूमते हुए दिख जाते हैं। जिनके आगे-पीछे कोई सुरक्षा घेरा नहीं होता। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाल में वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने के लिए कई कड़े निर्णय लिए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वे अपने फैसलों पर टिके रहेंगे। यहां मेरा आशय भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों आदि की आवश्यक सुरक्षा को लेकर कोई टिप्पणी करने का नहीं है। पर इनके अलावा देश में लगभग 19,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकारी सुरक्षा प्रदान की गई है। जिस पर 66,000 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। अकेले दिल्ली में 500 लोगों को वीआईपी सुरक्षा मिली है जिस पर लगभग 750 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है। अंदाजा लगाइए कि बाकी 18,500 लोगों की सुरक्षा पर कितने हजार करोड़ रुपया खर्च होता होगा? ये पैसा उस मतदाता की मेहनत की कमाई पर टैक्स लगाकर वसूला जाता है जिसे नर्मदा या वृंदावन की यमुना में सुरक्षा नियमों की लापरवाही के कारण बार-बार जान गंवानी पड़ती है। मुझे याद है कि 2003-05 में जब मैं वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर का अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर था तो मैंने वहां वीआईपी गाड़ियों के प्रवेश को रोकने के लिए दो मुख्य रास्तों के शुरू में ही लोहे की चेन लगवा दी थी जो आजतक लगी है। ऐसा मैंने तब किया जब संकरे प्रवेश मार्ग में मंदिर तक जाने को आमदा एक एसडीएम की गाड़ी ने एक वृद्ध महिला को कुचल दिया। गली के बाहर मैंने एक बोर्ड भी टंगवा दिया था। जिस पर लिखा था, 'बिहारी जी धनीनाथ या वीआईपीनाथ नहीं हैं वे दीनबंधु दीनानाथ हैं। उनके द्वार पर दीन बनकर आओगे तभी उनकी कृपा पाओगे।' मुझे खुशी है कि न सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों ने बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक ने इस नियम का पालन किया।

झारखंड - 'अबुवा सरकार' कब सुनेगी 'अबुवा जनता' की फ़रियाद!

एशिया का सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र कहे जाने वाले झारखंड स्थित 'सारंडा जंगल', खबरों के अनुसार विगत दिनों अर्ध सैन्यबलों की घेराबंदियों और गोलियों की आवाज़ों से थर्रा रहा। स्थापित नैरेटिव यही था कि यह सब इस क्षेत्र में उग्रवादी हिंसा समाप्त कर शांति और विकास के लिए था। जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सख्त फरमान भी जारी हुआ था। यह कहाँ तक सच और सही है इसकी वास्तविक पड़ताल ज़मीनी हकीकत से रु-ब-रु होकर ही की जा सकती है। फिलहाल सन्दर्भ है एक ऐसे मामले की चर्चा का जो है तो बिलकुल सामान्य सा लेकिन सत्ता-सियासत के साथ साथ प्रशासनिक पेंचों से ऐसा जटिल बनता जा रहा है कि इसी सारंडा क्षेत्र की जनता और शासन-प्रशासन आमने-सामने से हो गये हैं। विडंबनापूर्ण मामला है, इसी सारंडा क्षेत्र के जिला मुख्यालय चाईबासा शहर से जुड़ा। जहां इस नगर के निवासी विगत कई महीनों से शहर से जुड़ी भीड़-भाड़ वाली एक प्रमुख सड़क पर दिन में नो एंट्री लगाने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस सड़क पर 'नो एंट्री' लगाने की मांग की जा रही है उस पर हर समय भारी-बड़े वाहनों का पूरी रफ़्तार में लगातार आना-जाना लगा रहता है। जिससे वहां हर समय धूल-धुआं तो छाया ही रहता है और कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। क्योंकि घनी आबादी वाला इलाका होने के कारण इस सड़क पर हर समय आम नागरिकों और विशेषकर स्कूली बच्चों का आना-जाना लगा रहता है। फलतः चौबीसों घंटे तेज रफ़्तार से आ-जा रहे भारी वाहनों की चपेट में आकर आये दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। अब तक कई लोग अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं और अनेक घायल। हर दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों द्वारा तात्कालिक 'सड़क-जाम' एक एक मजबूरी सी बन गयी है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है कि दिन में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री लगायी जाय। चर्चा है कि इस सड़क से गुजरने वाले सभी भारी-बड़े वाहन औद्योगिक कॉरपोरेट घरानों के हैं इसलिए प्रशासन उनके खिलाफ जाने और 'नो एंट्री' लगाने से कतरा रहा है। गौरतलब है कि चाईबासा शहर के आसपास थर्मल-पावर और कई बड़े कल-कारखाने लगे हुए हैं। जिसके लिए कोयला समेत कई प्रकार के खनिज-अयस्क व रॉ-मेटेरियल भारी वाहनों से ही लाये-पहुंचाए जाते हैं। इलाके में कई प्रकार के खनन कार्य भी होते हैं जिनके खनिज-अयस्कों को रेल-वैगनों तक भी पहुंचाना रहता है। इस कारण हर दिन सैकड़ों भारी वाहनों के आने-जाने का सिलसिला विगत कई वर्षों से जारी है। फलतः आये दिन सड़क दुर्घटनाओं का होना एक स्थायी संकट बना हुआ है। हैरानी की बात ये है कि इस क्षेत्र के स्थानीय (झामुमो) विधायक राज्य की सरकार में 'परिवहन मंत्री' हैं, जिनका स्वतः संज्ञान लेना तो दूर उन्हें इस मसले से कोई मतलब ही नहीं दीखता। जबकि संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने लोगों से उनके हित में काम करने की घर-घर जाकर कसमें खायीं थीं। शहर की घनी आबादी से होकर भारी वाहनों के लगातार आने-जाने से हो रही पर्यावरण समस्याओं और आये दिन की जानलेवा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय शासन-प्रशासन से अनेक गुहार लगाने से लेकर राज्य सरकार और सम्बंधित विभागों को मांग-पत्र भेजा गया। जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। परेशान-हाल लोगों ने मजबूर होकर नो एंट्री आंदोलन समिति बनाकर शांतिपूर्ण आंदोलन करने के फैसला लिया। जिसकी शुरुआत पिछले साल 2025 के 27 सितम्बर को स्थानीय विधायक सह राज्य परिवहन मंत्री के चाईबासा नगर स्थित आवास पर धरना-प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें मांग-पत्र देने की घोषणा से की गयी। इसकी सूचना मंत्री जी को काफी पहले दे दी गयी थी लेकिन ऐन कार्यक्रम वाले दिन वे पहले ही वहां से निकल लिए। मीडिया से जारी पूर्व सूचना अनुसार नियत तिथि और समय पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिक अपने परिवार के सदस्यों के साथ धरने पर बैठ गए। जहाँ पहले से ही स्थानीय प्रशासन ने मंत्री जी के आवास और आस-पास में भारी पुलिस की तैनाती कर रखी थी। इस रवैये से लोगों में काफी नाराजगी फ़ैल गयी। धरना-प्रदर्शन शांतिपूर्वक ही चल रहा था लेकिन थोड़ी ही देर में प्रशासन ने जबरदस्ती हस्तक्षेप करना चाहा तो लोग भड़क उठे। बातचीत और सुलह-समझौते का कोई रास्ता अपनाने की बजाय लोगों को जबरन तितर-बितर करते हुए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। क्षुब्ध लोगों ने भी इसका तीखा विरोध किया। 28 लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ साथ 74 लोगों पर नामजद और 1500 अज्ञात लोगों पर संगीन धाराएँ लगाकर मुकदमा थोप दिया गया। इसके खिलाफ अगले ही दिन चाईबासा बंद कर व्यापक नागरिक प्रतिवाद प्रदर्शित किया गया। नो एंट्री आंदोलन के मुद्दों में अब सभी आन्दोलनकारियों पर लगाए गए झूठे मुकदमों की वापसी की मांग भी प्रमुख मुद्दा बन गया। जल्द ही चाईबासा शहर के साथ साथ इलाके में एक व्यापक समर्थन का जन अभियान बनने लगा। सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार अनसुना किये पर तय हुआ कि अब पद यात्रा निकालकर प्रदेश की राजधानी रांची पहुंचा जाय और मुख्यमंत्री से सीधा मिलकर बात की जाय। 'नो एंट्री आंदोलन समिति' के आह्वान पर बीते 26 अप्रैल से 1 मई तक न्याय-यात्रा/पद-यात्रा निकाली गयी। जो चाईबासा के ताम्बो चौक से शुरू हुई। इस यात्रा में शामिल आदिवासी युवाओं ने मीडिया को बताया कि कई स्थानों पर पुलिस-प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। चाईबासा से 150 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय कर लोग जब रांची स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास तक पहुंचना चाहे तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। वहां तैनात अधिकारी ने कहा कि- आप लोगों ने मिलने की अनुमति नहीं ली है इसलिए वे नहीं मिलेंगे। आंदोलनकारियों ने बताया कि कई दिन पहले ही आकर मुख्यमंत्री सचिवालय को लिखित सूचना दी गयी है। अधिकारी ने कहा कि आप अपना मांग-पात्र मुझे दे दीजिये, उनतक पहुंचा दिया जाएगा। सनद रहे कि मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे आंदोलनकारियों का नेतृत्व झारखंड समेत कोल्हान क्षेत्र के कई वरिष्ठ आदिवासी नेता कर रहे थे। जिसमें एकीकृत बिहार के समय के विधान सभा पूर्व उपाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ चम्पिया और पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप बालमुचु सरीखे राजनेता शामिल थे। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिले। अबुवा सरकार का ढोल पीटनेवालों द्वारा 'अबुवा जनता' के साथ की गयी सार्वजनिक उपेक्षा-अपमान से क्षुब्ध होकर आंदोलनकारी बिना किसी हो-हल्ला के वहां से वापस चल दिए। बाद में राज्यपाल से मिलकर उन्हें अपना मांग-पात्र सौंप दिया। इस पूरे प्रकरण में न्याय-यात्रा/पद-यात्रा में शामिल आदिवासी युवाओं में काफी गहरा क्षोभ और नाराज़गी देखी गयी।

जिनकी ये प्रतिक्रिया है- माननीय मुख्यमंत्री जी, हमलोग गाँधी जी के आदर्शों और विचारों को अमल में लाते हुए उनके सिद्धांतों के अनुरूप पदयात्रा कर आपके समक्ष आये हुए थे, किन्तु आपने हमसे न मिलकर उनके विचारों और संविधान का अपमान किया है! खबरों के अनुसार झारखंड भाकपा माले के राज्य नेताओं ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर नो एंट्री आंदोलन समिति की सभी मांगों का समर्थन देते हुए मांग पूरी होने तक आंदोलन में सक्रिय साथ देने की घोषणा की। चाईबासा से रांची पहुंचकर अबुवा सरकार से अपनी पीड़ा का समाधान की उम्मीदों को खुद मुख्यमंत्री द्वारा तोड़े जाने के बाद भी नो एंट्री आन्दोलन समिति ने अपना अभियान जारी रखने पर अडिग है। जानकारों के अनुसार यदि यह आन्दोलन जरा सा भी कड़ा तेवर लेता तो अबतक उग्रवादी हिंसा का ठप्पा लगाकर सारंडा क्षेत्र में तैनात केंद्र सरकार के अर्ध-सैन्यबलों के निशाने पर लाया जा चुका होता। क्योंकि अधिकांश आंदोलनकारी आदिवासी हैं।

युवा उद्यमी विकास अभियान से निखरा सोम देव बेकरी प्रोडक्शन

उत्तर प्रदेश की धरती में श्रम और स्वप्न का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसी स्वप्निल यात्रा को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी सीएम युवा योजना की नींव रखी है। यह योजना मात्र एक वित्तीय कार्यक्रम नहीं है बल्कि उन लाखों युवाओं के संकल्पों की संवाहिका है जो अपनी नियति स्वयं लिखने का साहस रखते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहाँ युवाओं की आबादी विकास का इंजन है, वहाँ उन्हें केवल रोजगार चाहने वाले के बजाय रोजगार प्रदाता के रूप में विकसित करना समय की माँग है। दमुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान इसी विजन को साकार करता है जिसमें युवाओं को वेतनभोगी नौकरियों के पीछे भागने के बजाय अपने सूक्ष्म और लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए एक अभूतपूर्व मंच प्रदान किया गया है। सरकारी तंत्र की यह संवेदनशीलता इस बात से स्पष्ट होती है कि इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बिना किसी गिरवी या कोलेटरल के 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय बाधाएं अक्सर बड़े सपनों के आड़े आती हैं लेकिन राज्य सरकार ने इस योजना में परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी देकर उस प्रारंभिक बोझ को भी कम कर दिया है जो एक नए उद्यमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। यह योजना विनिर्माण, सेवा और व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों को कवर करती है और समावेशी विकास के मंत्र पर आधारित है। इसमें समाज के हर वर्ग विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी गई है ताकि विकास की मुख्यधारा में कोई भी पीछे न छूटे। केवल धन की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं होती इसलिए सरकार ने परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से लेकर उद्यम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की भी पुख्ता व्यवस्था की है। इसी सरकारी प्रोत्साहन और अटूट व्यक्तिगत आत्मविश्वास का एक जीवंत उदाहरण जनपद एटा के गंगा नगर, असरौली के निवासी युवा उद्यमी श्री सोम देव हैं। श्री सोम देव उन युवाओं के लिए एक मशाल के समान हैं जो संसाधनों के अभाव में अपने हुनर को दबाए बैठे थे। सोम देव के मन में अपनी खुद की पहचान बनाने का एक छोटा सा लेकिन स्पष्ट सपना था। वे बेकरी उत्पादन के क्षेत्र में कुछ अनूठा करना चाहते थे लेकिन उनके मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध पूंजी का अभाव था। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने के कारण शुरुआती आर्थिक कठिनाइयों ने कई बार उनके हौसलों की परीक्षा ली। व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक मशीनरी, कच्चा माल और स्थान की व्यवस्था करना उनके लिए एक दुर्गम पहाड़ जैसा था। लेकिन जब उन्हें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में जानकारी मिली तो उन्हें अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई दिया। उन्होंने बिना देरी किए इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया और प्रदेश सरकार की सुगम ऋण प्रक्रियाओं का लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की मुख्य शाखा, एटा से ?4,37,500 का ऋण स्वीकृत कराने में सफल रहे। यह राशि केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं थी बल्कि श्री सोम देव के लिए वह खाद-पानी थी जिसने उनके सपनों के बीज को अंकुरित होने में मदद की। इस वित्तीय सहयोग के मिलते ही उन्होंने 'सोम देव बेकरी प्रोडक्शन' की स्थापना की। प्रारंभ में चुनौतियां कम नहीं थीं क्योंकि बाजार में पहले से स्थापित नामों के बीच जगह बनाना और ग्राहकों का विश्वास जीतना कठिन कार्य था। परंतु श्री सोम देव ने अपने उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने अपने बेकरी व्यवसाय में आधुनिकता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जिससे उनके द्वारा निर्मित बिस्कुट, केक और अन्य उत्पाद स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य के मानकों पर भी खरे उतरे।

धीरे-धीरे एटा के स्थानीय बाजारों में 'सोम देव बेकरी प्रोडक्शन' की महक फैलने लगी। ताजे और स्वादिष्ट उत्पादों की मांग इतनी बढ़ी कि उनके उत्पाद न केवल उनके गांव बल्कि आस-पास के शहरी क्षेत्रों में भी बेहद लोकप्रिय हो गए। आज सोम देव के चेहरे की चमक उनके परिश्रम और सरकार की कल्याणकारी नीतियों के सफल समन्वय की कहानी कहती है। श्री सोम देव की सफलता केवल उनकी निजी प्रगति तक सीमित नहीं है।

आज वे एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं और स्वयं आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ अन्य कई लोगों को अपने व्यवसाय में जोड़कर उन्हें आजीविका प्रदान कर रहे हैं। उनके इस कदम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और कई परिवारों के घरों में खुशहाली आई है। एक युवा जब अपने पैरों पर खड़ा होता है तो वह पूरे समाज को गति देता है और श्री सोम देव ने अपनी इस यात्रा से यह सिद्ध कर दिया है कि यदि इच्छाशक्ति प्रबल हो और शासन का सहयोग साथ हो तो कोई भी लक्ष्य अप्राप्य नहीं है।

उनकी बेकरी आज जनपद में एक मॉडल के रूप में देखी जाती है जहाँ अन्य युवा आकर प्रेरणा लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ने वास्तव में प्रदेश के जनपदों में जमीनी स्तर पर एक आर्थिक क्रांति का सूत्रपात किया है। यह योजना युवाओं के भीतर छिपी हुई उद्यमिता की ऊर्जा को पहचान कर उसे सही दिशा प्रदान कर रही है। एटा जैसे क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक व्यवसायों से इतर नए प्रयोगों की आवश्यकता थी, वहां सोम देव जैसे युवाओं ने इस सरकारी पहल को सफल बनाकर यह कर दिखाया है। सरकार की यह दूरदर्शी सोच कि युवाओं को आर्थिक स्वावलंबन से जोड़कर ही प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सकता है, आज धरातल पर श्री सोम देव जैसे हजारों लाभार्थियों के माध्यम से फलीभूत हो रही है। यह योजना न केवल वित्तीय ऋण दे रही है बल्कि युवाओं में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का वह जज्बा भर रही है जिससे वे चुनौतियों को अवसरों में बदलने का कौशल सीख रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान आज एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है जो युवाओं के भविष्य को सुदृढ़ करने के साथ-साथ उन्हें समाज में एक सम्मानित स्थान दिला रहा है। यह उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य की वह नींव है जहाँ हर युवा अपनी मेधा और मेहनत से सफलता के नए सोपान लिख रहा है और प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहा है। सोम देव की कहानी मात्र एक व्यक्ति की प्रगति नहीं है बल्कि यह प्रदेश सरकार के उन प्रयासों की जीत है जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास के शिखर तक ले जाने के लिए समर्पित हैं। यह अभियान प्रदेश के हर कोने में उद्यमिता की एक नई लहर पैदा कर रहा है जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भरता का एक वैश्विक केंद्र बनाएगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाटी ने कन्हा ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पंचशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार घाटी, मो : 09582083548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/XXXX)

बाढ़ व जलभराव नियंत्रण को लेकर प्रशासन सख्त, पम्पिंग स्टेशनों से लेकर नालों की सफाई तक व्यापक तैयारी

गोरखपुर।

नगर में संभावित बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। नगर निगम सभागार में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा व महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में नगर आयुक्त अजय जैन, जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, एसपी ट्रैफिक अमित श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों द्वारा बिंदुवार प्रस्तुतीकरण के माध्यम से तैयारियों की जानकारी दी गई।

पम्पिंग स्टेशनों की क्षमता बढ़ी, जल निकासी व्यवस्था मजबूत

प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि नगर क्षेत्र में स्थापित पम्पिंग स्टेशनों को पूरी तरह क्रियाशील रखा गया है। विभिन्न वार्डों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त पम्पिंग सेट लगाए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर और पम्प उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

नालों की सफाई तेज, अतिक्रमण हटाने के निर्देश

नगर निगम द्वारा प्रमुख एवं सहायक नालों की समयबद्ध सफाई कराई जा रही है। जहां जल निकासी में बाधा है, वहां अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए

गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर विशेष टीमें तैनात की गई हैं, ताकि बारिश के दौरान त्वरित कार्रवाई हो सके।

कंट्रोल रूम सक्रिय, हेल्पलाइन जारी

आपात स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम का कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर आमजन से अपील की गई है कि

मंडलायुक्त व महापौर की अध्यक्षता में समीक्षा, कंट्रोल रूम सक्रिय, संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर

जलभराव या बाढ़ की स्थिति में तुरंत सूचना दें। सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर त्वरित राहत सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

संचारी रोगों की रोकथाम पर विशेष ध्यान

बरसात के मौसम में फैलने वाले संचारी रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है। फॉगिंग, एंटी-लार्वा छिड़काव और साफ-सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी।

जनजागरूकता और राहत की तैयारी

नगरवासियों को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर राहत सामग्री, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बाढ़ एवं जलभराव से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बरकाती मस्जिद नौरंगाबाद में खुली मकतब इस्लामियात व दारुल कुरआन की नई शाखा

गोरखपुर।

बरकाती मस्जिद नौरंगाबाद गोरखनाथ में मकतब इस्लामियात व दारुल कुरआन शिक्षण संस्था की नई शाखा का उद्घाटन मुफ्ती-ए-शहर अख्तर हुसैन मन्नानी, शहर काजी मुफ्ती मुहम्मद अजहर शम्सी, मस्जिद के मुतवल्ली फिरोज अहमद व पार्षद नूर मुहम्मद ने किया। मुफ्ती-ए-शहर अख्तर हुसैन मन्नानी ने कहा कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। आलिम (ज्ञानी) की फजीलत इबादतगुजार पर वैसी ही है जैसे चौदहवीं के चांद की सितारों पर। एक सुदृढ़ समाज के निर्माण के लिए दीनी शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। दीनी शिक्षा इंसान को अल्लाह की इबादत, आखिरत की कामयाबी, हलाल व हराम और अच्छे-बुरे की समझ देती है, जबकि दुनियावी शिक्षा आधुनिक युग में आत्मनिर्भर बनकर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। दीनी शिक्षा हमारा रूहानी और नैतिक विकास करती है, इंसान को अल्लाह के करीब लाती है और जन्नत का रास्ता बताती है। मकतब इस्लामियात/दारुल कुरआन दीनी शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। इसमें अपने बच्चों का दाखिला जरूर करवाएं।

शिक्षा ही वह रोशनी है जो अज्ञानता के अंधेरे को मिटाती है : उलमा किराम

शहर काजी मुफ्ती मुहम्मद अजहर शम्सी ने कहा कि जो कौम शिक्षित और तकनीकी रूप से माहिर होती है, वही दुनिया में अपना मुकाम बना पाती है। दीनी शिक्षा जहां दिल और रूह को रोशन करती है, वहीं दुनियावी शिक्षा दिमाग और हाथों को हुनरमंद बनाती है। शिक्षा के इन दोनों रूपों का मेल अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी के लिए इन दोनों का होना जरूरी है। मकतब इस्लामियात/दारुल कुरआन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बच्चों को दोनों तरह की शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। मकतब इस्लामियात/दारुल कुरआन के संयोजक कारी मुहम्मद अनस नक्शबंदी व हाफिज रहमत अली निजामी ने कहा कि एक मुकम्मल और कामयाब इंसान बनने के लिए दीनी और दुनियावी शिक्षा का संतुलन बेहद जरूरी है। जहां दीनी शिक्षा हमें खुदा की पहचान और नैतिकता सिखाती है, वहीं दुनियावी शिक्षा हमें समाज में एक जिम्मेदार और हुनरमंद नागरिक बनाती है।दीनी शिक्षा इंसान की रूहानी और अखलाकी तरक्की के लिए बुनियादी चीज है। यह हमें अच्छे-बुरे और जायज-नाजायज के बीच फर्क करना सिखाती है। सही इल्म जन्नत के रास्ते को आसान बनाता है। धार्मिक शिक्षा हमें इंसानियत, बड़ों का एहतराम और दूसरों पर जुल्म न करने का पाठ पढ़ाती है। खुदा की रजा हासिल करने और इबादत के सही तरीकों को जानने के लिए यह शिक्षा लाजमी है। एक इंसान तभी पूरा होता है जब उसके पास अपने धर्म का ज्ञान हो और वह दुनियावी मामलों में भी माहिर हो। शिक्षा ही वह रोशनी है जो अज्ञानता के अंधेरे को मिटाती है। अभिभावकों को चाहिए कि वह अपने बच्चों को मकतब इस्लामियात/दारुल कुरआन में भेजें ताकि बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो सके।

साइबर सेल की बड़ी कामयाबी: ऑनलाइन ठगी के शिकार व्यक्ति के 3.43 लाख कराए वापस

गोरखपुर।

साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार एक आवेदक के खाते से निकाली गई कुल 3,43,896 की धनराशि को वापस दिलाया गया है। सुधीर जायसवाल पुलिस अधीक्षक (अपराध) के निर्देश पर साइबर सेल टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह सफलता प्राप्त की।

बिना ओटीपी साझा किए खाते से निकले पैसे

आवेदक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बैंक खाते से 8 बार में कुल 3,43,896 की रकम निकाल ली गई, जबकि उसने किसी को ओटीपी साझा नहीं किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल ने तत्काल जांच शुरू की।

तकनीकी विश्लेषण से मिला सुराग, बैंकों से समन्वय कराई रिकवरी

साइबर टीम ने तकनीकी विश्लेषण के जरिए धोखाधड़ी की प्रक्रिया का पता लगाया और संबंधित बैंकों व वित्तीय संस्थानों से समन्वय स्थापित किया। त्वरित प्रयासों के चलते पूरी धनराशि सफलतापूर्वक आवेदक के खाते में वापस करा दी गई।

टीम का सराहनीय योगदान

इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक साजिद अली खान, हेड कांस्टेबल शशिकांत जायसवाल, कांस्टेबल पंकज कुमार गुप्ता, कांस्टेबल अखिलेश कुमार और महिला आरक्षी दीप्ती सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ऑनलाइन लेन-देन से सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल या नजदीकी पुलिस से संपर्क करें।

राष्ट्रवाद भाजपा की मूल विचारधारा, कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी -विश्वरंजन कुमार आनन्द

विशुनपुरा, कुशीनगर।

भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, जो भारत को सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है। भाजपा का मूल मंत्र ÷व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा राष्ट्र है। राष्ट्रवाद के इसी सिद्धांत के कारण विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा की शक्ति उसके संगठन, कार्यकर्ताओं और विचार में निहित है। यह बातें भाजपा के जिला मंत्री विश्वरंजन कुमार आनन्द ने सोमवार को विशुनपुरा ब्लॉक सभागार में आयोजित विशुनपुरा मंडल की संगठनात्मक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, जो ÷राष्ट्र प्रथम÷ की भावना को अपना जीवन धर्म मानकर कार्य करता है। जिला मंत्री ने कार्यकर्ताओं से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर डबल इंजन सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाएं तथा पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करें। उन्होंने संगठन की ओर से मासिक मंडल बैठक, शक्ति केंद्र बैठक, बूथ बैठक एवं प्रधानमंत्री Narendra Modi के 'मन की बात' कार्यक्रम को नियमित रूप से आयोजित करने पर जोर दिया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व जिला उपाध्यक्ष धनजय तिवारी ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि यह प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है।

बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष चौहान ने की, जबकि संचालन मंडल महामंत्री जवाहर पाल ने किया। अंत में पूर्व मंडल अध्यक्ष कपिल देव लाल श्रीवास्तव ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राधेश्याम गुप्ता, विवेक पाण्डेय, हीरालाल कुशवाहा, संजय राय, श्रीकांत जायसवाल, उगनी देवी, संजीव उपाध्याय, सुरेंद्र जायसवाल, पूनम कुशवाहा, योगेंद्र चौहान, इश्वरदेव शर्मा, शैलेश गुप्ता, कृष्ण बिहारी गोंड सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जनता पर बोझ डालना ही अब सरकारी नीति — प्रधानमंत्री के बचत वाले आह्वान पर सांसद का विस्फोटक पलटवार

देवरिया।

सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी ने सोमवार को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे जनता के साथ क्रूर मजाक करार दिया। प्रधानमंत्री द्वारा खाद्य तेल, पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कटौती करने की अपील पर पलटवार करते हुए सांसद ने कहा कि देश अब सरकार चलाने से नहीं, बल्कि आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ डालने की रणनीति पर चल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के हालिया बयानों को 12 साल की नाकाम नीतियों का खुला कबूलनामा बताते हुए कहा कि जिस सरकार को महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगानी चाहिए थी, वह अब

सांसद रमाशंकर राजभर ने प्रधानमंत्री के बचत वाले आह्वान को बताया जनता पर बोझ; बोले— महंगाई और बेरोजगारी रोकने में नाकाम सरकार अब दे रही कम जीने का ज्ञान

अपनी विफलताओं का ठीकरा जनता के सिर फोड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिकंदराबाद के कार्यक्रम में खाद्य तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा बचाने के तर्क को आड़े हाथों लेते हुए सांसद राजभर ने कहा कि सरकार के पास देश की चरमराती अर्थव्यवस्था का कोई ठोस समाधान नहीं बचा है। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि कभी सोना न खरीदने की बात होती है, तो कभी विदेश न जाने की सलाह दी जाती है।

अब हद तो यह है कि जनता को तेल और खाद तक कम इस्तेमाल करने का ज्ञान बांटा जा रहा है। सांसद ने सवाल उठाया कि क्या एक मजबूत नेतृत्व का काम रोजाना जनता से नए-नए त्याग मांगना है? उन्होंने कहा कि कम खर्च करो और कम जियो जैसी सलाह उन करोड़ों परिवारों के लिए अपमानजनक है जो पहले से ही बेतहाशा महंगाई की मार झेल रहे हैं। सांसद रमाशंकर राजभर ने आगे कहा कि प्राकृतिक खेती और पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने जैसे उपदेश केवल अपनी रणनीतिक हार को छिपाने के बहाने हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश मजबूत नीतियों और विजन से चलता है, न कि नागरिकों की थाली से तेल कम करवाकर। सरकार की जिम्मेदारी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए निर्यात और उत्पादन पर ध्यान देने की थी, लेकिन सरकार अब आम आदमी की बुनियादी जरूरतों पर कैंची चलाने को देशभक्ति का नाम दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता अब इन खोखले तर्कों और बहानों को समझ चुकी है और अर्थव्यवस्था के इस गंभीर मोड़ पर सरकार की चुप्पी उसकी प्रशासनिक विफलता को प्रमाणित करती है।

ट्रेन से गिरा अधेड़ रातभर ट्रैक किनारे तड़पता रहा, सुबह महिलाओं और बच्चों की नजर पड़ी तो बची जान

गोरखपुर।

बढ़नी-गोरखपुर रेल मार्ग पर पीपीगंज स्टेशन से आगे तिघरा रेलवे क्रासिंग के पास रविवार रात में ट्रेन से गिरा अधेड़ पूरी रात रेलवे ट्रैक किनारे घायल अवस्था में पड़ा रहा। सोमवार सुबह शौच के लिए गई महिलाओं और बच्चों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी तो उसे अस्पताल पहुंचाया गया। महराजगंज जिले के कोल्हुई स्थित महेशपुर टोला मेहँदिया निवासी 50 वर्षीय सर्वजीत रविवार रात ट्रेन से गोरखपुर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रेन जैसे ही पीपीगंज स्टेशन से आगे बढ़ी और तिघरा रेलवे क्रासिंग के पास पहुंची, तभी ट्रेन से नीचे गिर गए। सिर में गंभीर चोट लगने से वह अचेत हो गए। रात होने के कारण किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी और वह पूरी रात रेलवे ट्रैक किनारे घायल अवस्था में पड़े रहे। सोमवार सुबह करीब सात बजे बगहीभारी और गोलीगंज गांव की महिलाएं और बच्चे शौच के लिए रेलवे ट्रैक की ओर गए थे। इसी दौरान लोगों की नजर ट्रैक किनारे घायल पड़े अधेड़ पर पड़ी। सूचना मिलते ही पीपीगंज कस्बा चौकी प्रभारी आदित्य सिंह मौके पर पहुंचे। घायल अधेड़ को उपचार के लिए जंगल कौड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां उसका उपचार चल रहा है। एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि घायल की पहचान होने के बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई। परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए हैं।

अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, क्लब से निकलते ही दबोचे गए शूटर; हाशिम और राशिद गैंग के लिए करते थे काम

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में संगठित अपराध और गैंगवार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन गैंग-बस्ट 2.0 के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर राशिद केबल वाला और तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा गिरोह के छह सक्रिय गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 10 अवैध हथियार और 81 कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए सभी बदमाश हत्या, रंगदारी और जानलेवा हमले जैसे जघन्य अपराधों में शामिल रहे हैं। क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदौरा का कहना है कि इंस्पेक्टर प्रकाश चंद की टीम दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय गिरोहों पर नजर रख रही थी। तभी छह मई को पुलिस टीम को जानकारी मिली कि राशिद केबल वाला और हाशिम बाबा गिरोह के सदस्य करोल बाग स्थित एफ-बार एंड लॉज में जमा हुए हैं। सार्वजनिक सुरक्षा और क्लब के भीतर भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बाहर ही मौजूद रही। तड़के 4.5 बजे जैसे ही चार बदमाश क्लब से बाहर निकलकर मारुति बलेनो कार की ओर बढ़े, पुलिस टीम ने उन्हें दबोच लिया।

रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई

वहीं, कार की तलाशी लेने पर चार पिस्टल (दो इटली निर्मित बेरेटा पिस्टल शामिल) और 32 कारतूस बरामद हुए। बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने दो और सक्रिय बदमाशों इमरान उर्फ तेली और अरविंद उर्फ छोटा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से भी अवैध हथियार बरामद किए। इनकी निशानदेही पर और हथियार व कारतूस बरामद किए गए। चारों के पास से नौ पिस्टल और प्वाइंट 32 बोर की विदेशी व स्वदेशी पिस्टल, एक राइफल, 81 कारतूस, एक मारुति बलेनो कार बरामद की गई।

दुबई में छिपे थे ये सभी शूटर

वहीं, जांच में पता चला कि ये सभी शूटर दुबई में छिपे थे और राशिद केबल वाला के सीधे संपर्क में थे। पुलिस की नजरों से बचने के लिए ये लोग सिग्नल एप का इस्तेमाल करते थे। राशिद इन्हें सट्टा कारोबार चलाने, क्लबों से रंगदारी वसूलने और विरोधी गिरोहों के बदमाशों की हत्या करने के निर्देश देता था। राशिद केबल वाला दिल्ली पुलिस का मोस्टवांटेड अपराधी है। वह जेल में बंद हाशिम बाबा का करीबी सहयोगी है और वर्तमान में दुबई से गिरोह को आपरेट कर रहा है। उसका नाम कई हत्याकांड में आया है। जिनमें ग्रेटर कैलाश एक में चर्चित नादिर शाह हत्याकांड (सितंबर 2024), पूर्वी दिल्ली दोहरा हत्याकांड (दिवाली 2024), कृष्णा नगर के व्यापारी सुनील जैन हत्याकांड (दिसंबर 2024) शामिल है। गिरफ्तार बदमाशों में नवाजिश, इस गिरोह का मुख्य हथियार संचालक बताया गया। इसने 2024 में प्रीत विहार के ब्लैक पैंथर कैफे में फायरिंग की थी। इसके पास से पांच हथियार बरामद हुए हैं। माज के मामा अपराधी हैं वह जेल में बंद हैं। जान खतरे में देखकर वह गिरोह में शामिल हुआ और क्लबों से वसूली का काम देखने लगा।

पीएम की 24 घंटे में दूसरी अपील- डेस्टिनेशन वेडिंग से बचें, ऑनलाइन क्लासेज चुनें; फिर किया ईंधन बचाने का आह्वान

वडोदरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में लगातार दूसरी बार देशवासियों से तेल की बचत करने की अपील की है। उन्होंने वडोदरा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट पिछले कई वर्षों के सबसे गंभीर संकटों में से एक है। उन्होंने विश्वास जताया कि जैसे भारत ने कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक उबरकर आगे बढ़ा, वैसे ही इस संकट से भी देश बाहर निकलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, ताकि देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके। उन्होंने संबोधन से पहले %सरदारधाम-3% शैक्षणिक संकुल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन किसी पवित्र त्योहार से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने से पहले वे सोमनाथ मंदिर भी गए थे, जहां उन्हें सोमनाथ मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर

प्रधानमंत्री ने बताया, क्या करें-क्या न करें

आयोजित अमृत महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना सरदार पटेल के संकल्प से ही पूरा हुआ था। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक धरोहर भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है।

ईंधन बचत पर पीएम की अपील- सार्वजनिक परिवहन अपनाएं, सोना खरीद टालें

उन्होंने यह भी कहा कि जब भी देश पर युद्ध या कोई बड़ी आपदा आई है, तब नागरिकों ने सरकार के आह्वान पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है और अब भी इसी एकजुटता की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयास किए जाएं और ऐसे व्यक्तिगत खर्चों से बचा जाए जिनमें विदेशी मुद्रा का उपयोग होता है। पीएम ने एक बार फिर से लोगों से अपील की कि ईंधन की खपत कम करें और निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाएं या इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि लोग फिलहाल सोना खरीदने जैसी गैर-जरूरी खर्च वाली चीजों को टालें, ताकि देश की आर्थिक स्थिरता को मजबूती मिल सके। उन्होंने स्कूलों में अस्थायी रूप से ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की सलाह भी दी, ताकि मौजूदा परिस्थितियों में शिक्षा व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

छोटे-छोटे कदमों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं

पीएम मोदी ने कहा कि पहले भी जब देश युद्ध या किसी बड़े संकट से गुजरा है, तब हर नागरिक ने सरकार के आह्वान पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आज भी सभी लोगों को मिलकर देश के संसाधनों पर बोझ कम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत कई वस्तुओं के आयात पर लाखों करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा खर्च करता है, जबकि आयातित वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे एक-एक बूंद मिलकर घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हमें विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करनी चाहिए और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे खर्चों से बचना चाहिए जिनमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर छोटे-छोटे कदम उठाने होंगे ताकि बाहरी चुनौतियों के बावजूद देश की प्रगति पर कोई असर न पड़े।

छुट्टियां भारत में बिताएं

पीएम ने कहा कि छुट्टियां शुरू होते ही कई परिवार बच्चों को लेकर विदेश घूमने निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग और विदेश यात्रा का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। पीएम मोदी ने कहा कि अब कई लोग विदेश में शादी करने की पुरानी आदत छोड़ रहे हैं, जो एक सकारात्मक बदलाव है। उन्होंने लोगों से सवाल करते हुए कहा कि क्या भारत में घूमने के लिए सुंदर और ऐतिहासिक जगहों की कमी है? उन्होंने कहा कि देश के भीतर ही ऐसी कई जगहें हैं जहां बच्चे भारत के इतिहास, संस्कृति और विरासत को करीब से जान सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपनी छुट्टियां भारत में बिताएं, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा दें और देश की संस्कृति पर गर्व महसूस करें।

राहुल बोले- देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से की गई सात अपील पर निशाना साधा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझौता करने वाला बताया। उन्होंने लिखा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे- सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये

सोना न खरीदें, विदेश न जाएं जैसी 7 अपीलें उपदेश नहीं; नाकामी के सबूत

उपदेश नहीं- ये नाकामी के सबूत है। उन्होंने आगे लिखा, 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है- क्या खरीदें, क्या न खरीदें, कहां जाएं, कहां न जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं, ताकि खुद की जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब समझौता करने वाले प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं।

सहारनपुर में मूर्ति विवाद पर भड़की हिंसा, मायावती ने सरकार को घेरा: बोलीं- दलितों को बनाया गया निशाना, हो निष्पक्ष कार्रवाई

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने सहारनपुर जिले के लालवाला गांव में हुई हिंसा पर चिंता जताते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने सोमवार को एक्स पर लिखा कि सहारनपुर के एक गांव में एक भूमि पर मूर्ति रखने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो बाद में संघर्ष में बदल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में दलित समाज के कई लोग घायल हुए हैं। बसपा अध्यक्ष ने पुलिस और प्रशासन से मामले में तत्काल तथा निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग करते हुये कहा कि प्रशासन को हालात पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने दोनों पक्षों से भी संयम बरतने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

उन्होंने कहा कि मामले को ताकत के बजाय कानूनी तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्र में तनाव न बढ़े और शांति कायम रह सके। गौरतलब है कि सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के लालवाला गांव में 9-10 मई को लगभग दो बीघा जमीन पर कब्जे और कथित तौर पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान पत्थरबाजी और लाठीचार्ज में तीन महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घटना के बाद गांव में सुरक्षा बलों की तैनाती कर निगरानी बढ़ा दी है।

पंजाब राजनीतिक में आप को बड़ा झटका, सीएम भगवंत के भाई ज्ञान सिंह ने थामा बीजेपी का दामन

चंडीगढ़। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के छह अन्य सांसदों के बाद, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए हैं।

पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में आयोजित इस समारोह में उपस्थित थे। ज्ञान सिंह का भाजपा में शामिल होना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अभियान

रणनीतिकार रहे हैं। आगामी नगर निकाय चुनावों से ठीक पहले, एक महत्वपूर्ण समय पर पार्टी में शामिल होने का उनका निर्णय पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के भाई होने के बावजूद, ज्ञान सिंह ने पहले भी राज्य प्रशासन की आलोचना की है, विशेष रूप से पंजाब में आई बाढ़ से निपटने के तरीके की, और दावा किया है कि प्रशासनिक विफलताओं ने जनता की पीड़ा को और बढ़ा दिया। एक कार्यकर्ता और पूर्व आम आदमी पार्टी रणनीतिकार के रूप में, उन्होंने अक्सर सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों का उपयोग करके सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों पर सवाल उठाए हैं, और अक्सर ऐसे रुख अपनाए हैं जो पार्टी के आधिकारिक रुख के विपरीत थे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उनके इस निर्णय से भाजपा को शासन और आंतरिक मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी प्रशासन पर हमले करने में और मजबूती मिलेगी। एक कार्यकर्ता और पूर्व आम आदमी पार्टी रणनीतिकार के रूप में, उन्होंने अक्सर महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों पर सवाल उठाने के लिए सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों का इस्तेमाल किया, और अक्सर ऐसे रुख का समर्थन किया जो पार्टी की आधिकारिक स्थिति के विपरीत थे।

बीएसएफ को बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन मिलेगी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिन के भीतर यह जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। दरअसल कोलकाता में नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। सीएम अधिकारी ने कहा कि यह फैसला बैठक में लिए गए मुख्य प्रस्तावों में से एक था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार ने राज्य में पुराने IPC और CrPC की जगह नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता को लागू नहीं किया था। राज्य में अब BNS लागू करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना भी पश्चिम बंगाल में भी लागू की जाएंगी। पहली कैबिनेट बैठक में मंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशिथ प्रमाणिक, क्षुदिराम और अशोक कीर्तनिया मौजूद थे। अभी तक मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे गए हैं। चुनावी हिंसा में मारे गए 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसे 45 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। दआयुष्मान भारत योजना समेत केंद्र की सभी योजनाएं जल्द ही लागू होंगी। उज्ज्वला योजना से जुड़ी सभी लंबित याचिकाएं केंद्र के पास भेजी गई हैं। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल ट्रेनिंग की परमिशन दी जाएगी। बंगाल में बीएनएस लागू नहीं था, राज्य में इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।

-कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा-

प्रधानमंत्री मोदी की 7 अपीलों के बाद लगेगा महंगाई का झटका, बढ़ेंगी ईंधन की कीमते

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों से की गई सात अपीलें पश्चिम एशिया संकट से जुड़ी आर्थिक कठिनाइयों के बीच ईंधन की कीमतों में वृद्धि और मितव्ययिता उपायों की शुरुआत का संकेत हो सकती है। एक्स पर पोस्ट करते हुए रमेश ने कहा कि हैदराबाद में मोदी के संबोधन के दौरान की गई टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि आर्थिक स्थिति सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार की गई स्थिति से कहीं अधिक गंभीर हो सकती है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री द्वारा कल हैदराबाद से देश की जनता से की गई अप्रत्याशित अपील का मतलब निम्नलिखित हो सकता है – 1. आर्थिक स्थिति आधिकारिक आंकड़ों और प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा अब तक किए जा रहे दावों से कहीं अधिक

गंभीर है। 2. ईंधन की कीमतों में वृद्धि सहित कड़े मितव्ययिता उपायों को जल्द ही लागू किया जा सकता है और उन्हें अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। रमेश ने जमीनी आर्थिक वास्तविकता और सरकार के विकास और स्थिरता के दावों के बीच के अंतर की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि यह बात लंबे समय से स्पष्ट है कि जमीनी आर्थिक स्थिति - उदाहरण के तौर पर वास्तविक वेतन में ठहराव, बढ़ते घरेलू कर्ज और रोजगार सृजन करने वाले निजी निवेश में गति की कमी - मोदी सरकार के प्रचार से बिलकुल अलग है। प्रधानमंत्री ने पिछले दिन सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नागरिकों से आयात पर निर्भरता कम करने और जिम्मेदार उपभोग अपनाने का आग्रह किया, ताकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण बढ़ती लागत के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। मोदी की अपीलों में खाद्य तेल की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, कार-पूलिंग को प्राथमिकता देने, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और आयात कम करने तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने का आह्वान शामिल था।

31 सीटों पर बीजेपी की जीत को लेकर टीएमसी का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा दावा

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने सोमवार को दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) में किए गए विलोपन ने पश्चिम बंगाल के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में परिणामों को काफी हद तक प्रभावित किया है। यह दावा सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान किया गया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, टीएमसी नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बताया कि 31 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की टीएमसी पर जीत का अंतर एसआईआर निर्णय प्रक्रिया में मतदाता सूची से हटाए गए व्यक्तियों की संख्या से कम था। उन्होंने आगे कहा कि कई मामलों में हटाए गए व्यक्तियों की संख्या और हार का अंतर लगभग बराबर था। बनर्जी ने बताया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार 862 वोटों से हार गया, जहां निर्णय के लिए 5432 से अधिक व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी और भाजपा के बीच वोटों का अंतर लगभग 32 लाख था और लगभग 35 लाख अपीलें अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित थीं। सांसद ने न्यायमूर्ति बागची द्वारा पहले की गई उस टिप्पणी का भी हवाला दिया कि यदि जीत का अंतर हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम है, तो मामले की न्यायिक जांच की आवश्यकता हो सकती है।

चुनाव आयोग ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि इसका उपाय चुनाव याचिका है और मतदान आयोग को एसआईआर से संबंधित मुद्दों और वोटों के जोड़ने या हटाने के खिलाफ परिणामी अपीलों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का जवाब

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोग अपने दावों के संबंध में नए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि परिणामों के बारे में आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं...जिन पर विचाराधीन निर्णयों के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो सकता है...उसके लिए एक स्वतंत्र अंतरिम आवेदन (आईए) की आवश्यकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने पीठ को बताया कि मौजूदा रफ्तार से अपीलीय न्यायाधिकरणों को अपीलों का निपटारा करने में कम से कम 4 साल लगेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होगी कि अपीलों का निपटारा शीघ्रता से किया जाए।

होर्मुज में फिर बढ़ेगा तनाव? सीजफायर बहुत कमजोर स्थिति में

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष विराम (सीजफायर) को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह सीजफायर अब बहुत कमजोर स्थिति में है और लाइफ सपोर्ट पर टिका हुआ है। ट्रंप ने यह बयान उस समय दिया जब उनसे ईरान के साथ चल रही शांति प्रक्रिया और प्रस्ताव को लेकर सवाल पूछा गया था।

ट्रंप ने ठुकराया ईरान का जवाब

ट्रंप ने ईरान के हालिया जवाब को खारिज करते हुए उसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि

डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया ईरान का प्रस्ताव

उन्होंने ईरान के प्रस्ताव को पढ़ा और वह बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पर किसी तरह का दबाव नहीं है और देश पूरी जीत की ओर बढ़ रहा है।

शांति प्रयासों के बावजूद बढ़ा तनाव

ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों से शांति बहाली की कोशिशें जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। फरवरी 28 से शुरू हुए संघर्ष के बाद कई क्षेत्रों में तनाव बढ़ा है। अप्रैल में दोनों पक्षों के बीच

ट्रंप ने यह बयान उस समय दिया जब उनसे ईरान के साथ चल रही शांति प्रक्रिया और प्रस्ताव को लेकर सवाल पूछा गया था।

अस्थायी सीजफायर पर सहमति बनी थी, लेकिन स्थिति अब भी स्थिर नहीं है।

शांति प्रस्ताव पर तेहरान की शर्तें

ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, तेहरान ने अपने जवाब में युद्ध रोकने की बात कही है। ईरान चाहता है कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम हो। साथ ही, उसने होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की शर्त रखी है। अमेरिका ने पहले यह प्रस्ताव दिया था कि अन्य संवेदनशील मुद्दों जैसे परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने से पहले दोनों देश शत्रुता समाप्त करें।

परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर विवाद

अमेरिका लगातार ईरान से अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने की मांग कर रहा है। इसके बदले में प्रतिबंध हटाने और फ्रीज किए गए धन को रिलीज करने की बात कही गई है। वार्ता में होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने का मुद्दा भी शामिल है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का अहम मार्ग है। इस रास्ते से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की आपूर्ति होती है।

वैश्विक बाजारों पर असर की आशंका

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो इसका असर तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ सकता है।